आय पर करों के संबंध में
दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन
को रोकने के लिए जापान की सरकार
तथा भारत गणराज्य की सरकार
के बीच अभिसमय
का संशोधनकारी प्रोटोकॉल।

आय पर करों के संबंध में
दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन
को रोकने के लिए जापान की सरकार
तथा भारत गणराज्य की सरकार
के बीच अभिसमय
का संशोधनकारी प्रोटोकॉल।

जापान की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार,

24 फरवरी, 2006 को टोक्यो में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल (इसके बाद "अभिसमय" कहा गया है) द्वारा यथा संशोधित 7 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए जापान की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 तथा 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3. पैराग्राफ 2 के अनुबंधों में किसी बात के होते हुए, करार करने वाले राष्ट्र में उत्पन्न होने वाला ब्याज दूसरे संविदाकारी राष्ट्र में ही कराधीन होगा यदि:

- (क) ब्याज, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र की सरकार, उसकी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण, या उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक या पूरी तरह से उस सरकार की स्वामित्व वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त और लाभदायक ढंग से स्वामित्व में है; अथवा
- (ख) ब्याज, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र की सरकार, उसकी किसी राजनीतिक उप-प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक या पूरी तरह से उस सरकार की स्वामित्व वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्याभूत, बीमित या अप्रत्यक्ष रूप

से वित्तपोषित ऋण-दावों के संबंध में उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के किसी निवासी द्वारा प्राप्त और लाभदायक ढंग से स्वामित्व में है।

4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ, शब्दों, “केन्द्रीय बैंक” और “उस सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली वित्तीय संस्था” का आशय:

(क) जापान के मामले में:

- (i) बैंक ऑफ जापान;
- (ii) जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन;
- (iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी;
- (iv) निप्पोन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस;
- (v) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसकी पूंजी संविदाकारी राष्ट्रों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमति के अनुसार जापान की सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है;

(ख) भारत के मामले में:

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक;
- (ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक;
- (iii) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया;
- (iv) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड;
- (v) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसकी पूंजी संविदाकारी राष्ट्रों की सरकारों के बीच समय-समय पर सहमति के अनुसार भारत की सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।”

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अनुच्छेद 26 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुच्छेद 26

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा

संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, यदि ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों संविदाकारी राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत आपूर्तिकर्ता संविदाकारी राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार सम्बंधी, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक राज़ अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि

संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद 3

अभिसमय के अनुच्छेद 26 के बाद निम्नवत रूप से एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा:

“अनुच्छेद 26 क

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए अनुच्छेद 2 में शामिल तथा निम्नलिखित करों से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है:

(क) जापान में:

- (i) उपभोग कर;
- (ii) विरासत कर; और
- (iii) उपहार कर;

(ख) भारत में:

- (i) संपत्ति कर;

- (ii) उत्पादशुल्क;
 - (iii) सेवा कर;
 - (iv) बिक्री कर; और
 - (v) मूल्य वर्धित कर;
- (ग) कोई अन्य कर जिस पर संविदाकारी राज्यों की सरकारें सहमत हुई हों।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा खुद अपने करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य कानूनों के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा था जो दूसरे संविदाकारी राज्य को इस पैराग्राफ के तहत एक अनुरोध करने की शर्त को पूरी करता हो।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस संविदाकारी राज्य में किसी समय सीमा के अध्यक्षीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. पैराग्राफ 5 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए, पैराग्राफ 3 या 4 के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किसी राजस्व दावे के संग्रहण में किसी संविदाकारी राष्ट्र द्वारा किए गए कार्य, जो, यदि दूसरे संविदाकारी राष्ट्र द्वारा किए गए थे, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानून के अनुसार राजस्व दावे पर लागू समय-सीमा को निलंबित या हस्तक्षेप करने का प्रभाव होगा, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानून के तहत इस प्रकार का प्रभाव होगा। पहला उल्लिखित संविदाकारी राष्ट्र ऐसे कार्यों के बारे में दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को सूचित करेगा।

7. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

8. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

(क) पैराग्राफ 3 के तहत अनुरोध के मामले में, प्रथम-वर्णित संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा, जोकि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में है जोकि उस समय, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत इसके संग्रहण का निवारण नहीं कर सका या

(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है

प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

9. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति के विपरीत हों;

- (ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- (घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस संविदाकारी राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।”

अनुच्छेद 4

1. यह प्रोटोकॉल प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्रों की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित होगा और इस प्रकार का अनुमोदन दर्शाते हुए राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान की तारीख के बाद तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 द्वारा यथा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा:

(क) जापान में:

(i) किसी कराधीन वर्ष के आधार पर लगाए गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी कराधीन वर्ष हेतु करों के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और

(ii) किसी कराधीन वर्ष के आधार पर नहीं लगाए गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लगाए गए करों के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और

(ख) भारत में:

(i) स्रोत पर रोक कर रखे गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 अप्रैल को या उसके बाद भुगतान या क्रेडिट की गई राशि के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है; और

(ii) कैलेण्डर वर्ष की 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है।

3. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 द्वारा यथा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद 26 और प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 द्वारा जोड़े गए अभिसमय के अनुच्छेद 26क के उपबंध, उस तारीख, जिस तारीख को कर लगाए गए या

कराधीन वर्ष, जिससे कर संबंधित हैं, पर ध्यान दिए बिना, प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. यह प्रोटोकॉल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अभिसमय लागू रहता है।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में ग्यारह दिसम्बर, 2015 को जापानी, हिन्दी और अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

जापान की

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

सरकार की ओर से

K. Hiramatsu

Hasmukh Adhia